

# महंगाई, घरेलू जरूरत के आधार पर होगा चीनी निर्यात का फैसला

आगामी सीजन में 400 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान

सुरेंद्र प्रसाद सिंह • नई दिल्ली

जिस बाजार में महंगाई, घरेलू खपत, एथनाल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली मात्रा और कैरीओवर स्टॉक के आकलन के बाद ही सरकार चीनी निर्यात पर फैसला करेगी। चीनी उद्योग ने सरकार से 80 लाख टन चीनी निर्यात के साथ कोटा प्रणाली के बजाए ओपेन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) श्रेणी में डालने का आग्रह किया है। सरकार एक अक्टूबर को नया पेरॉई सत्र शुरू होने से पहले चीनी निर्यात से जुड़ी घोषणा कर सकती है।

आगामी पेरॉई सीजन के चालू होने के समय चीनी का ओपनिंग स्टॉक पिछले कई सालों के निचले स्तर 60 लाख टन पर है। चालू सीजन 2021-22 के दौरान कुल 112 लाख टन चीनी का निर्यात किया जा चुका है। जबकि अगले चीनी वर्ष 2022-23 के दौरान 80 लाख टन से अधिक चीनी निर्यात की संभावना नहीं है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने आगामी पेरॉई सीजन में कुल 400 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान जताया है। वर्ष 2021-22 के दौरान 394 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। उद्योग संगठन का कहना है



- चीनी उद्योग ने निर्यात की मात्रा 80 लाख टन तक रखने का आग्रह किया
- चीनी निर्यात को कोटा प्रणाली के बजाए ओजीएल में डालने की भी मांग
- 45 लाख टन चीनी एथनाल बनाने में इस्तेमाल होगी, घरेलू खपत 275 लाख टन

## सरकार के सामने स्टॉक बढ़ाने की चुनौती

आगामी पेरॉई सीजन में 400 लाख टन चीनी उत्पादन होने का अनुमान जरूर व्यक्त किया गया है। लेकिन इस बार एथनाल उत्पादन में 45 लाख टन चीनी इस्तेमाल का अनुमान है। जबकि चीनी की घरेलू खपत 275 लाख टन

होने का अनुमान है। इस हिसाब से 80 लाख टन निर्यात के बाद अगले सीजन (2023-24) का कैरीओवर स्टॉक फिर वही 60 लाख टन ही बचेगा। लिहाजा सरकार के पास निर्यात स्टॉक को बढ़ाने का विकल्प नहीं बचा है।

कि चीनी निर्यात के एडवांस सौदे होने से मिलों के समक्ष नकदी संकट नहीं होगा और गन्ना किसानों को आगामी सीजन में भुगतान में मुश्किल नहीं आएगा। इसी के मद्देनजर चीनी उद्योग संगठन ने सरकार से आगामी सीजन में चीनी निर्यात को ओजीएल की श्रेणी में रखने का आग्रह किया है, ताकि चीनी मिलें निर्यात के अनुबंध कर सकें।

**घरेलू बाजार में चीनी का मूल्य नहीं बढ़ने देना चाहती सरकार:** दरअसल, सरकार महंगाई के दौर में घरेलू

बाजार में चीनी की कीमतों नहीं बढ़ने देना चाहेगी। खाद्य मंत्रालय और चीनी उद्योग के बीच इस बारे में विस्तार से वार्ता हो चुकी है। मंत्रालय चीनी की मांग और आपूर्ति का आकलन करा रहा है। इसके बाद ही सरकार अक्टूबर और नवंबर में चीनी निर्यात के तौर तरीके बारे में कोई पुख्ता फैसला ले सकती है। फिलहाल सरकार चीनी निर्यात के लिए कोटा प्रणाली अपना रही है। जबकि चीनी उद्योग ने इसे ओजीएल में रखना चाहता है।